भारत के वाणिज्य दूतावासों में हिन्दी को बढ़ावा

@3060. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारत के वाणिज्य दूतावास कितने हैं और उनमें राजभाषा के प्रयोग, प्रचार और प्रसार के संबंध में स्थिति क्या है और उनमें देवनागरी लिपि के टंकण यंत्रों, हिन्दी टंककों और आशु-लिपिकों तथा आधुनिक टेलेक्स, कम्प्यूटरों और टेलीप्रिन्टरों की क्या व्यवस्था की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : विदेशों में भारत के 25 प्रधान कोंसलावास तथा 5 कोंसलावास हैं।

विदेश स्थित हमारे राजदूतावासों तथा उच्चायोगों की भांति ही भारत के प्रधान कोंसलावासों तथा कोंसलावासों को भी राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का पालन करने तथा हिन्दी का यथासंभव प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। विदेशों में हिन्दी का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी भारत के राजदूतावासों की तरह भारत के प्रधान कोंसलावासों और कोंसलावासों पर भी है। इस दिशा में हमारे कुछ कोंसलावासों ने सराहनीय कार्य किया है और हिन्दी के क्षेत्र में कार्यरत कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को बहुमूल्य सहायता दी है।

बसरा, शिराज, जहिदान तथा हरारे स्थित कोंसलावासों को छोड़कर सभी प्रधान कोंसलावासों तथा कोंसलावासों को देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए हैं।

देवनागरी टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर, तथा कम्प्यूटर सप्लाई नहीं किए गए हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता अभी महसूस नहीं की गई है।

जहां तक हिन्दी टंककों और आशुलिपिकों का संबंध है, उनकी तैनातियों पर मिशन की आवश्यकता के आधार पर विचार किया जाता है। जब कभी भी अनुरोध प्राप्त होते है तो इस प्रकार के कार्मिकों को तैनात करने के प्रयास किए जाते हैं।

@Previously Unstarred Question 2127, transferred from the 15th March, 1988.

SC/ST employees in Indian Navy

3061. KUMARI SUSHILA TIRIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the number of Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees in Indian Navy as on the 29th February, 1988;

(b) whether Government propose to increase reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Navy; and

(c) if so, what percentage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) As on 29th February, 1988, 4514 Scheduled Castes and 867 Scheduled Tribes civilian employees were borne on the strength of the Indian Navy. As regards the uniformed personnel, there is no reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the Armed Forces.

(b) Does not arise in view of answer to part (a) above.

(c) Does not arise.

Propellent Factory

3062. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

SHRI AJIT P. K. JOGI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Propellent Factory in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is likely to be set up either in West Bengal or Madhya Pradesh; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) A proposal to this effect is under consideration of Government.

(c) and (d) No decision regarding the location of the proposed propellant factory has yet been taken by the Government.

Health problems of women in areas surrounded by Nuclear Reactors

3063. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the danger of health problems for women in areas surrounding nuclear power reactors;

(b) whether studies similar to those in USA have been carried out in India; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Government is aware of a report in this regard appearing in "Clarity" Weekly of February 7-13, 1988 alleging fall in birth rate due to radiation in the vicinity of Nuclear Power Stations.

(b) and (c) No, Sir.

However, adequate safety margins have been built into the formulation of safety standards with special provisions for control of radiation exposure to women in the reproductive age group. Comprehensive medical surveys have been carried out on employees and family members who reside in the departmental colonies in the vicinity of nuclear power stations. Based on these medical records it can be said that there are no indications of any increase in the incidence of disease|ailments|fall in birth rate etc. Government are also aware of reports about the increased incidence of certain diseases due to ionising radiation around nuclear installations abroad. However, special committees appointed to go into the statistics and validity of the statements have ruled that there are no definite evidences to suggest increased occurrences of diseases in the vicinity of nuclear power plants due to radiation.

उड़ीसा में गरीबी दूर करने की योजनाएं

3064. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उड़ीसा में गरीबी दूर करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में उ जिलो के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित इस योजना पर 1988-89 के वर्ष के दौरान कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन इंगती) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में गरीबी उन्मूलन की कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है । तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सहित देश में जिन तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है, वे है---एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन